

प्रदेश आख्यात/पास



भारत

टीबी के लक्षणों को न करें नजरंदाज़: सदर विधायक

(आधुनिक समाचार नेटर्क)

रायबरेली। राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम (एनटीईपी) के तहत जनपद में सात दिसंबर से 100 दिवसीय सघन टीबी अभियान शुरू किया है जिसका उद्देश्य है टीबी रोगियों का पता लगाकर उन्हें तत्काल उपचार करना।

क्रम में मुख्यमंत्री योगी आदियनाथ ने पूरे प्रदेश से 100 दिवसीय सघन टीबी अभियान शुरू किया है जिसका उद्देश्य है टीबी रोगियों का पता लगाकर उन्हें तत्काल उपचार करना।



इसी क्रम में बृथकर को फिरोज गांधी कॉलेजी स्थित पार्क में जगरूकता कार्यक्रम आयोजित हुआ था कार्यक्रम में मुख्य अधिकारी सदर विधायक अदियनाथ ने एक संवादित सिंह ने लोगों को संबोधित करें हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने साल 2025 तक देश से क्षय रोग के उन्मूलन का लक्ष्य रखा है। इसी

18 जनवरी को पोर्टल पर कृषि यंत्रों की बुकिंग करने वाले किसानों को ई-लॉटरी के माध्यम से किया जायेगा चयन

(आधुनिक समाचार नेटर्क)

रायबरेली। उप कृषि निदेशक विनोद कुमार ने बताया है कि सब मिशन अन एप्रील और मैकेनाइजेशन एवं समर्त यंत्रीकरण योजनान्तर्मत वित्तीय वर्ष 2024-25 में कृषि यंत्रों के वितरण से सम्बन्धित कृषकों के चयन हेतु जिलाधिकारी मोहदद्या रायबरेली की अधिक्षता में गठित समिति के सदस्यों की उपस्थिति में 18 जनवरी 2025 को कृषि भवन

1:00 बजे से ई-लॉटरी का आयोजन किया गया, जिसमें <https://agriculture.uped.goved.gov.in> पर ऑनलाइन बुकिंग करने वाले जनपद के कृषकों द्वारा प्रतिभाग किया जायेगा। कृषि यंत्रीकरण योजनान्तर्मत समस्त यंत्रों यथा-रोटोवेटर, कल्टीवेटर, थ्रेसर, लेजर लैंड लेवलर, चारा काटने की मशीन, स्पाल गोदाम, थ्रेसिंग फ्लोर, कस्टम हायरिंग सेन्टर की स्थापना इत्यादि हेतु ई-लॉटरी के माध्यम

तहसील सलोन में तालाबों को 10 वर्षीय मत्स्य पालन पट्टा नीलामी 30 व 31 जनवरी को 15 दिनों के अन्दर जमा करना अनिवार्य होगा। सभी बोलीदाता आय निवास प्रमाण पत्र जो 06 माह से अधिक पुराना न हो बोली के संयुक्त प्रस्तुत करना होगा। सभी प्रस्तुत करने वाले राजस्व संहित 2006 के नियम 57 व 58 द्वारा की जायेगी जो तहसील मुख्यालय / राजस्व परिषद की बेसाइट <https://bor.uped.niced.in> पर उपलब्ध है। सर्वोच्च बोली बोलने से लाभ सिविल/व्यक्ति को नीलामी धनराशि एवं वर्ष के लिए नीलामी का 1/4 भाग तुरन्त जमा करना होगा। शेष 3/4 भाग नीलामी तिथि के अधिकार मेरे की जाएगी।

बच्चों को सघन टीबी अभियान के तहत किया जायेगा जागरूक

(आधुनिक समाचार नेटर्क)

रायबरेली। राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन टीपीसी अभ्यंतरी ने बच्चों को शपथ

टीपीसी के बारे में बताया साथ ही डीपीसी अभ्यंतरी ने बच्चों को शपथ



कार्यक्रम (एनटीईपी) के तहत जनपद में 7 दिसंबर से 100 दिवसीय सघन टीबी अभियान चलाया जा रहा है। जिसमें आज जनपद के विभिन्न कॉलेज में टीबी कार्यक्रम किये गए, जिसमें महात्मा गांधी इंटर कॉलेज रायबरेली में भी जगरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में 100 प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा साल 2025 तक देश से क्षय रोग के उन्मूलन का लक्ष्य रखा है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री योगी आदियनाथ ने पूरे प्रदेश में 100 दिवसीय सघन टीबी अभियान शुरू किया है जिसका उद्देश्य है टीबी रोगियों का पता लगाकर उन्हें तत्काल उपचार पर लाना व टीबी से होने वाली मौतों को रोकना।

आधुनिक गेट हाउस

- वाटर प्रूफ शेड
- पार्किंग की सुविधा
- मन्दिर की सुविधा
- सी.सी.टी.वी.
- छोटे-बड़े कार्यक्रमों के अलग-अलग रेट
- 45000 sq. feet. एरिया
- हरे-भरे वातावरण
- AC कमरा (VIP)

CALL: 9519313894, 9415608783, 9415608710

आधुनिक समाचार पब्लिशिंग हाउस, यूपीएसआईडीसी, रेमण्ड रोड, औद्योगिक थाने के पीछे भारत पेट्रोलियम के पहले, औद्योगिक क्षेत्र, नैनी, प्रयागराज

एडीएम (प्रशासन) की अध्यक्षता में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की जिला स्तरीय सलाहकार समिति की बैठक सम्पन्न

(आधुनिक समाचार नेटर्क)

रायबरेली। अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) सिद्धार्थ की अध्यक्षता में कलेक्टर स्थित बचत भवन सभागार में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की जिला स्तरीय सलाहकार समिति की बैठक सम्पन्न हुई। अपर जिलाधिकारी ने कहा कि जनसामान्य के बताया कि दो सप्ताह से अधिक खासी आना, खासते वक्त बलगम के साथ खन आना, लातार रजन कम होना, भूख न लगना, शाम के समय बुखार आना तथा रात में पसीना आना आदि यह टीबी के लक्षण हैं। इसीलिए टीबी खांसा नहीं यह लाइन नहीं है। निरीक्षण इलाज और पॉलिक थोजन के सेवन से ठीक हो जाती है। इसीलिए टीबी खांसा नहीं यह लाइन नहीं है। निरीक्षण व छापे मारते समय विशेष सावधानी बतायी जाए। प्रमुख पर्व व त्योहारों में कलेक्टर बैठक में खाद्य पदार्थों एवं औषधियों में मिलावट और अधोमानकता के प्रति जनसामान्य में जगरूकता बढ़ाये जाने के उद्देश्य से उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों

की जानकारी दिये जाने हेतु महावर्षी सूचना एवं तथ्यों को प्रचारित एवं प्रसारित किया जाए। अपर जिलाधिकारी ने कहा कि खाद्य पदार्थों एवं औषधियों में मिलावट और अधोमानकता के अनुरूप हुई। अपर जिलाधिकारी ने कहा कि जनसामान्य को सुरक्षित एवं मानक के अनुरूप खाद्य पदार्थों एवं औषधियों को उपलब्धता सुनिश्चित किये जाने के दृष्टिकोण से असुरक्षित एवं अधोमानक खाद्य पदार्थों तथा नकली व अधोमानक दवाओं की रोकथाम सम्बन्धी समस्त आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करायी जाये। निरीक्षण व छापे में वृद्धि की जाए, और ज्यादा से ज्यादा नमूने जांच हेतु संग्रहित किए जाए। निरीक्षण व

की जानकारी दिये जाने हेतु महावर्षी सूचना एवं तथ्यों को प्रचारित एवं प्रसारित किया जाए। अपर जिलाधिकारी ने कहा कि जैसे बैसगर की धरती के अपर शहीद लालचन्द्र स्वर्णकार ने अपने

लालचन्द्र स्वर्णकार शोध संस्थान के अध्यक्ष सूर्य कुमार बाजपेई ने कहा कि बैसगर की धरती के अपर शहीद लालचन्द्र स्वर्णकार ने अपने करेगी तो उसे पूर्त रूप दिया जाएगा। इस अवसर पर लालचन्द्र स्वर्णकार के प्रोफेसर हरिश्चकर सोनी को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम

(आधुनिक समाचार नेटर्क)

रायबरेली। रायबरेली, अमर शहीद लालचन्द्र स्वर्णकार के शहीद स्थल मन्दिर में जिला

लालचन्द्र स्वर्णकार शोध संस्थान के अध्यक्ष सूर्य कुमार बाजपेई ने कहा कि बैसगर की धरती के अपर शहीद लालचन्द्र स्वर्णकार ने अपने



प्रशासन, गवर्नर शाहित देश का गोरव बढ़ाया है, उन्हें कोटि-कोटि नमन के संयुक्त प्रस्तुत करना होगा। सभा का आयोजन किया गया। समारोह के मुख्य अतिथि भारत सेवक समाज के अध्यक्ष शिव नारायण सोनी ने कहा कि अमर शहीद लालचन्द्र स्वर्णकार ने देश की आजादी में अपने प्राण न्यौतावर किया है। गंत प्रधान सुरेश कुमार यादव ने कहा कि हमारी गंत सभा बारह बिस्ता जमीन अमर शहीद लालचन्द्र स्वर्णकार के बलिदान संग्राम पूरे परिवार का बलिदान दिया है, ऐसे महान देश भक्त को हम प्रस्तुत करता है। सरकार मदद के आयोजन में गांव पचायत अधिकारी अनुराग पांडे का योगदान रहा। इस अवसर पर लालचन्द्र स्वर्णकार के बैठक में वर्ष 2024-25 का पुनरीक्षित बजट एवं वर्ष 2025-26 में रुपये 8798.86 लाख एवं वर्ष 2025-26 के मूल बजट रुपये 6022.00 लाख का अनुमोदन किया गया है एवं वर्ष 2025-26 में प्राप्त होने वाली बजट की अद्यता अधिकारी राजेन्द्र प्रसाद द्वारा किया गया। बैठक में वर्ष 2025-26 में रुपये 8798.86 लाख एवं वर्ष 2025-26 के मूल बजट रुपये 6022.00 लाख का अनुमोदन किया गया है एवं वर्ष 2025-26 में प्राप्त होने वाली बजट की अद्यता अधिकारी राजेन्द्र प्रसाद द्वारा किया गया। बैठक में सदन के मार शहीद लालचन्द्र स्वर्णकार की धनराशि से कराये जाने वाले कार्यों की सुची मार शहीद लालचन्द्र स्वर्णकार के बलिदान संग्राम के बारे में बताया गया।

के आयोजन में गांव पचायत अधिकारी अनुराग पांडे का योगदान रहा। इस अवसर पर लालचन्द्र स्वर्णकार के बैठक में वर्ष 2024-25 का पुनरीक्षित बजट एवं वर्ष 2025-26 में रुपये 8798.86 लाख एवं वर्ष 2025-26 के मूल बजट रुपये 6022.00 लाख का अनुमोदन किया गया है एवं वर्ष 2025-26 में प्राप्त होने वाली बजट की अद्यता अधिकारी राजेन्द्र प्रसाद द्वारा किया गया। बैठक में सदन के मार शहीद लालचन्द्र स्वर्णकार की धनराशि से कराये जाने वाले कार्यों की सुची म

सम्पादकीय

भरोसा बढ़ाने वाले फैसलों की प्रतीक्षा,
बजट से जनता को कई उम्मीदें

मादा सरकार इध्यशाक्त ता दिखा रही है लेकिन यह कहना कठिन है कि वह विभिन्न क्षेत्रों में सुधारों को समय रहते आगे बढ़ा सकेगी। अच्छा हो कि मोदी सरकार अगले माह जो बजट पेश करने जा रही है उसके जरिये न केवल यह दिखाए कि बहुमत से दूर रहने के बाद भी वह एक सक्षम सरकार है और अपने एजेंडे को लागू करने के लिए अदिग है। पिछले लोकसभा चुनाव में जब नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा को अपने बलबूते बहुमत नहीं मिला तो इसके कायास लगाए जाने लगे कि गठबंधन सरकार उस बैग और लचीलेपन के साथ कार्य नहीं कर पाएगी, जैसा पिछले दो कार्यकालों में दिखा था। गठबंधन सरकार की अपनी मजबूरियां होती हैं। तीसरी पारी में मोदी सरकार को अपना एजेंडा इसे ध्यान में रखकर बढ़ाना है कि वह नीतीश कुमार की जदयू और चंद्रबाबू नायडू की तेलुगु देशम पार्टी के समर्थन पर निभर है। मोदी सरकार अपने तीसरे कार्यकाल के लगभग सात माह पूरे कर चुकी है। इस दौरान ऐसा लगा कि वह कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों द्वारा तय किए जा रहे नैरेटिव और उनके विरोध के कारण उस गति से आगे नहीं बढ़ पा रही है, जिसकी अपेक्षा की थी। यह साफ दिख रहा है कि उसे वक्फ अधिनियम, एक देश-एक चुनाव पर विपक्ष के दबाव का सामना करना पड़ रहा है। इसकी भी अनदेखी नहीं की जा सकती कि मोदी सरकार ने अपने तीसरे कार्यकाल का अपना जो पहला बजट पेश किया, उसमें ऐसे क्रांतिकारी कदम नहीं दिखे, जो देश की मूलभूत समस्याओं का निराकरण कर पाते। यदि संसद के पिछले सत्रों को देखा जाए तो मोदी सरकार महत्वपूर्ण समझा जाने वाला एक मात्र बिल-भारतीय वायुयान विधेयक ही पारित करा सकता है। पिछली सरकारों की तरह मोदी सरकार भी रह-रहकर होने वाले विधानसभा चुनावों का सामना करती है। बार-बार चुनावों के चलते सत्तापक्ष को विपक्ष को जवाब देने के लिए उस जैसे ही तौर-तरीके अपनाने पड़ते हैं। कई बार तो उसे न चाहते हुए भी वह सब करना पड़ता है, जो आर्थिक दृष्टि से सही नहीं होता। भाजपा को वैसी जन कल्याणकारी योजनाएं घोषित करनी पड़ी हैं, जैसी विपक्षी दलों ने वोट हासिल करने के लिए घोषित कीं। महिलाओं को मासिक भुगतान देने का जो चलन शुरू हुआ है, उससे अब कोई भी दल अछूता नहीं है। महिलाओं को आकर्षित करने वाली इन योजनाओं के कारण ही महाराष्ट्र में भाजपा को प्रचंड जीत मिली। मध्य प्रदेश, हिमाचल, कर्नाटक और झारखंड में भी ऐसी योजनाएं वोट हासिल करने का जरिया बनीं। अब दिल्ली में आम

बड़ी विसंगति से मुक्त हुई स्कूली
शिक्षा, सीखने की प्रक्रिया पर
देना होगा आधिक ध्यान

वर्ष 1992 में आई यशपाल कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार बच्चों के स्कूल छोड़ने के पीछे हृद्दब्स्ते का बोझ़ और विदेशी भाषा लादा जाना सबसे प्रमुख कारण है। फेल न करने की नीति के चलते शिक्षक गरीब बच्चों के प्रति और भी लापवाह होते जा रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे उनके पास-फेल होने के लिए वे जिम्मेदार ही नहीं हैं। यह स्वागतयोग्य है कि शिक्षा का अधिकार कानून, 2009 की एक बड़ी विसंगति को केंद्र सरकार ने दूर कर दिया। अब नए सत्र से पाचर्वी और आठर्वी कक्षा की परीक्षा पास करने वाले छात्र ही अगली कक्षाओं में जा सकेंगे। वर्ष 2010 से पूरे देश में आठर्वी तक की कक्षाओं को पास-फेल के नियम से मुक्त कर दिया गया था। ऐसा इस सीमित तर्क की आई में किया गया था कि फेल होने से बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं, उनका मनोबल गिर जाता है और तनाव में आ जाते हैं। इसलिए बिना परीक्षा के ही उन्हें अगली कक्षा में प्रमोट किया जा रहा था। ठीक है कि शिक्षा का अर्थ केवल परीक्षा नहीं है और परीक्षा के तनाव से छात्रों को मुक्त भी रखा जाना चाहिए, लेकिन इस नियम ने स्कूली शिक्षा को तो नुकसान पहुंचाया ही, कालेज शिक्षा को भी बर्बाद कर दिया। इसका सबसे बुरा असर देश भर के सरकारों स्कूलों पर हुआ। ज्यादातर सरकारी स्कूलों में उन गरीब परिवारों के बच्चे पढ़ते हैं, जिनकी आर्थिक-सामाजिक स्थिति अच्छी नहीं होती। उनके पास अपने बच्चों की शिक्षा की तरफ ध्यान देने के लिए न वक्त होता है, न सामर्थ्य। कोई बच्चा घर से तो स्कूल चला गया, लेकिन वह वास्तव में स्कूल में गया या नहीं या उसने क्या पढ़ाई की, इसकी जानकारी तभी मिलेगी, जब वह परीक्षा देने के बाद पास या फेल होगा। आठर्वी तक फेल न करने की नीति के चलते बच्चे अगली कक्षा में तो पहुंच जा रहे थे, लेकिन उनमें से कइयों को आता-जाता कुछ भी नहीं था। इससे अगली कक्षा के शिक्षकों के सामने भी कई समस्याएं खड़ी होने लगी थीं। नीतिज्ञन स्कूली शिक्षा में और भी गिरावट आती गई। पिछले एक दशक से प्रथम और इस जैसी दूसरी संस्थाओं के सर्वे बार-बार यह रेखांकित कर रहे थे कि आठर्वी के बच्चे को चौथी क्लास का गणित नहीं आता या पांचर्वी का बच्चा दूसरी क्लास की हिंदी की किताब भी नहीं पढ़ सकता। ऐसी रपटें आने के बाद दो-चार दिन तो शिक्षा व्यवस्था पर कुछ प्रश्न उठते, लेकिन उसमें सुधार के बारे में कभी गंभीरता से नहीं सोचा जाता। ऐसे में निजी स्कूल सरकारी स्कूलों के मुकाबले और आगे बढ़ते चले जा रहे थे। जिन सलाहकारों ने बच्चों को स्कूल न छोड़ने देने के लिए फेल न करने का आसान रास्ता अपनाया, उन्होंने ऐसा कोई सुझाव नहीं दिया, जिससे इस समस्या को दूर किया जा सकता। जब यही बच्चे नौवीं-दसवीं में कई-कई बार

सड़कों पर क्यों ठोकरें खाता है सरकारी नौकरी का खाब

सरकारी नौकरी पाने का युवाओं का खाब अमूमन इस तरह सड़कों पर दर-दर की ठोकरें खाने पर क्यों मजबूर है? देश के अधिकांश राज्य लोक सेवा आयोग अक्षमता के शिकार हैं, ऐसा क्यों बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी) के परीक्षार्थियों का प्रारंभिक परीक्षा रद्द करने का आंदोलन तीन हफ्ते बाद भी समाप्त नहीं हो रहा है तो इसको लेकर कई सवाल उठने लगे हैं। पहला तो यह राज्यों में सरकारी नौकरी पाने का युवाओं का खाब अमूमन इस तरह सड़कों पर दर-दर की ठोकरें खाने पर क्यों मजबूर है? दूसरा, देश के परीक्षार्थियों के सड़कों पर उतरने के पीछे कोई चिंता है, क्योंकि वो सभी प्रतियोगी परीक्षाएं अपनी सुविधा और स्वार्थ के हिसाब से करवाना चाहते हैं, न होने पर आंदोलन करवा देते हैं। उधर यह राजनीतिक मुद्दा भी बन गया है। शुरू में कुछ विपक्षी दलों ने आंदोलनकारी परीक्षार्थियों के साथ खड़ा दिखने की कोशिश की, लेकिन बाद में जन सुराज पार्टी के प्रशांत किशोर द्वारा आंदोलन को हाईजैक करता देख, दूसरे दलों ने इससे दूरी बना ली। सत्तारूढ़ एनडीए के घटक दल तो इस आंदोलन को शुरू से प्रायोजित और नीतीश सरकार रहा है, इसका न तो कोई जवाबदेह है और न ही किसी को इसकी चिंता है। जबकि यह देश के युवाओं के भविष्य से जड़ा गंभीर मुद्दा है। बीपीएससी की कहानी भी इससे अलग नहीं है। वहां बरसों बाद बड़े पैमाने पर द्वितीय श्रेणी के सरकारी पदों पर भर्तियां निकली थीं। लेकिन उसमें भी अफरा तफरी हड्डी। बताया जाता है कि बीपीएससी में पेपर लीक का विवाद परीक्षा के बापू सेंटर से शुरू हुआ। वहां कुछ पेपर कम पड़ गए थे तो दूसरे केन्द्र से मंगवाने पड़े। जिससे कई परीक्षार्थियों को थोड़े समय के अंतर से पेपर मिले। यकीन यह बीपीएससी की बड़ी बाद समाप्त हुआ था। वहां परीक्षार्थी यूपीपीएससी द्वारा नार्मलाइजेशन प्रक्रिया के बजाए पर्सटाइल पद्धति से परीक्षा कराने, पूरी परीक्षा एक ही पाठी में कराने की मांग को लेकर आंदोलन पर उतरे थे। बता दें कि नार्मलाइजेशन से तात्पर्य किसी भी परीक्षा में परीक्षार्थियों की तादाद बहुत ज्यादा होने पर आयोजक दो पालियों में परीक्षा कराते हैं। ऐसे में अगर पहली पाली का पेपर कठिन आता है और उसमें अधिकार्थियों के कम नंबर आते हैं तो दूसरी पाली का पेपर थोड़ा आसान होता है और उसमें



अक्षमता के शिकार हैं, ऐसा क्यों उनके द्वारा भर्ती किए जाने वाले कल के अफसरों और अन्य कर्मचारियों के चयन की शुचिता क्यों नहीं रह पाती है? ऐसा होने के लिए जिम्मेदार कौन है, सरकारी नौकरी का सपना देखने वाले या फिर इन रुआबदार नौकरियों के लिए परीक्षा आयोजित करने वाले? तीसरे, इन धांधलियों पर लगाम कब लगेगी और कौन लगाएगा बीपीएससी की 70 वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा (सीपीई) के पेपर लीक होने की खबर के बाद से गुस्साए परीक्षार्थी सड़कों पर उतरे हुए हैं और पटना के गर्दनीबाग में धरना दे रहे हैं। गड़बड़ी की गंभीर शिकायतों के बीच बीपीएससी ने 4 जनवरी को री-एग्जाम (पुनर्परीक्षा) भी आयोजित की, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ, क्योंकि परीक्षार्थियों को बीपीएससी पर ही भरोसा नहीं है। (हालांकि किसी संस्था पर से भरोसा उठ जाना भी समस्या के समाधान में मददगार नहीं होता।) व्यवस्था और तंत्र पर आपको कुछ तो याकीन रखना ही होगा। बीपीएससी ने इतना जरूर माना कि बापू परिसर परीक्षा केन्द्र पर पेपर लीक हुआ, लेकिन उसने समूची परीक्षा रद्द करने से इंकार कर दिया। शक यह भी है कि हैं। हालांकि कुछ राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अगर मामला नहीं सुलझा तो परीक्षार्थियों का यह आंदोलन मिनी अन्ना आंदोलन में भी तब्दील हो सकता है, जो सत्तारूढ़ एनडीटी के लिए खतरे की घंटी है। परीक्षा आयोजन में प्रौद्योगिकी का बढ़ता इस्तेमाल उसकी शुचिता, पारदर्शिता और त्वरितता के लिए कम, हेराफेरी के लिए ज्यादा होता दिख रहा है। अबल तो राज्यों में सरकारी भर्ती के विज्ञापन ही कम निकलते हैं। निकले भी तो उसमें दस गलतियां होती हैं या जानबूझकर की जाती हैं। मान लीजिए कि विज्ञापन के बाद प्रतियोगी परीक्षा की तारीखें घोषित हो भी गई तो तय तिथि को परीक्षा हो जाए तो खुद को किस्मत वाला समझिए। अगर परीक्षा भी समय पर हो गई तो परीक्षा के पेपर लीक होना, पर्चे बिकना, फिर रिजल्ट बरसों लटकें रहना, रिजल्ट भी आ जाए तो नियुक्ति पत्र मिलने के लिए बरसों इंतजार करने की मजबूरी अब आम बात हो गई है। केवल यूपीएससी की परीक्षाएं काफी हद तक बेहतर ढंग से हो रही हैं। वरना अन्य प्रतियोगी परीक्षा के अभ्यर्थियों को हर बात में इंसाफ के लिए या तो सड़कों पर आना पड़ता है या फिर कोर्ट की शरण लेनी पड़ती है। ऐसा क्यों हो संख्या में परीक्षार्थियों को प्रश्नपत्र भी उपलब्ध नहीं करा सकता तो इसे क्या कहा जाए? इस बीच खबर फैली कि पेपर लीक हो चुका है। यह सुनते ही छात्र भड़क गए और उन्होंने पेपर का बहिष्कार कर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। इस बीच एक आंदोलनकारी को पटना डीएम ने तमाचा जड़ दिया। उधर बीपीएससी का कहना है कि मामला चूंकि एक ही सेंटर का था इसलिए पूरी परीक्षा रद्द करने का सवाल ही नहीं है। लेकिन इस दलील पर परीक्षार्थियों को भरोसा नहीं हो रहा। उनका आंदोलन उग्र हो गया तो पुलिस ने लाठियां भी बरसाईं। अब जन सुराज पार्टी के प्रशांत किशोर इस आंदोलन के पुरोधा बनकर अपनी सियासी जमीन तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। इस बीच कुछ अन्य नेताओं जैसे तेजस्वी यादव आदि ने भी शुरू में आंदोलनकारियों से सहानुभूति जताई, लेकिन बाद में हाथ खींच लिया। अब परीक्षार्थियों का कहना है कि वे मुद्दे को लेकर हाई कोर्ट जाएंगे। कूलमिलाकर बिहार पीएससी परीक्षार्थियों को कोई राहत जल्द मिलेगी, ऐसा लगता नहीं है। हमने पिछले साल नंबरबार में उत्तर प्रदेश पीएससी के परीक्षार्थियों का आंदोलन भी देखा, जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हस्तक्षेप के हैं तो कठिन पेपर गाली पाली के अभ्यर्थियों के नंबर में थोड़ी बढ़ोतरी कर दी जाती है। यही नार्मलाइजेशन कहलाता है। विरोध कर रहे अभ्यर्थियों का कहना था कि यह खेल के बीच नियम बदलने जैसा है और इसमें धांधली की पूरी गुजाइश है। लिहाजा समूची परीक्षा एक ही पाली में कराई जाए। सवाल यह है कि जब यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा एक पाली में कराती है तो राज्य सेवा आयोग ऐसा क्यों नहीं कर सकते इसी तरह बीते दिसंबर में मप्र के इंदौर में 'नेशनल एजुकेटेड यूथ यूनियन' के बैनर तले एमपीएससी के अभ्यर्थियों ने न्याय यात्रा निकाली थी। उनकी मांग थी कि एमपीएससी की 2019 की मुख्य परीक्षा की कॉपियां दिखाई जाएं और इसकी मार्कशीट जारी की जाए। साथ ही सभी विज्ञापित पदों पर एक साथ भर्ती की जाए। आंदोलनकारियों ने इंदौर में मप्र लोक सेवा आयोग के मुख्यालय पर धरना भी दिया। बाद में सरकार वें दखल वें बाद अभ्यर्थियों ने आंदोलन समाप्त किया। इसी तरह महाराष्ट्र में ठाकरे राज में महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग द्वारा प्रस्तावित परीक्षाएं कोरोना के कारण रद्द करने पर नाराज अभ्यर्थियों ने राज्यपाली आंदोलन किया था।

डिजिटल भारत की आकांक्षाओं का प्रतीक, डाटा संरक्षण अधिनियम से सबको मिलेगा फायदा

आधारित सहमति, डाटा मैटाने को सुविधा और डिजिटल रूप में नामंकित व्यक्ति को नियुक्त करने की क्षमता आदि। नागरिक अब उल्लंघनों या अनधिकृत डाटा उपयोग

ज्ञान कुछ भी हो, अपने आधिकाराओं को समझ सकता है और उनका प्रयोग कर सकता है। सहमति स्पष्ट शब्दों में मांगी जाती है तथा नागरिकों को अंग्रेजी या संविधान

के व्यक्तिगत डाटा का इस्तेमाल करने के लिए माता-पिता या अभिभावक की सत्यापन योग्य सहमति को अनिवार्य बनाते हैं। अतिरिक्त सुरक्षा उपाय बच्चों को

को गाथा रहो है और हम इस गात को बनाए रखने के प्रति दृढ़ हैं। हमारी रुपरेखा डिजिटल अर्थव्यवस्था में नवाचार को सक्षम करते हुए नागरिकों के लिए

वना को दबाया न जाए, जो स्टार्टअप और व्यवसायों को रक्ती है। नई व्यवस्था से व्यवसायों और स्टार्टअप के सुपालन बोझ कम हो जाएगा।

हो, बाल्क हमार सामाजिक-आधिक परिदृश्य की अनूठी चुनौतियों के अनुकूल भी हो। यह सुनिश्चित करने के लिए कि नागरिक अपने अधिकारों और जिम्मेदारियों के बारे में ज्ञानकूल हैं, ज्ञानिकों को उनके



डाटा सरकार जावानिम, 2025 ताग हो जाएगा, जो नागरिकों के व्यक्तिगत डाटा सुरक्षा के अधिकार और रक्षा के लिए हमारी प्रतिबद्धता को रेखांकित करेगा। भारतीय नागरिक ही डीपीडीपी नियम, 2025 के केंद्र में हैं। डाटा के बढ़ते वर्चस्व लाली दुनिया में हमारा मानना है कि व्यक्तियों को शासन की रूपरेखा के केंद्र में रखना अनिवार्य है। ये नियम नागरिकों को कई अधिकारों के सामने असहाय महसूस नहीं करेंगे। उनके पास अपनी डिजिटल पहचान को प्रभावी ढंग से सुरक्षित रखने के उपय होंग। इससे संबंधित नियमों को सरलता एवं स्पष्टता के साथ तैयार किया गया है। इसमें सुनिश्चित किया गया है कि प्रत्येक

में सूचीबद्ध 22 भारतीय भाषाओं में से किसी में भी जानकारी देना अनिवार्य बनाया है। यह रूपरेखा समावेशिता के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाती है। आज के इस डिजिटल युग में बच्चों की विशेष देखभाल की आवश्यकता है। इसे शोषण, अनधिकृत प्रोफाइल बनाने और अन्य डिजिटल नुकसान से बचाव सुनिश्चित करते हैं। ये प्रविधान भविष्य की पीढ़ी के लिए एक सुरक्षित डिजिटल परिदृश्य बनाने के प्रति हमारे समर्पण को दर्शाते हैं। भारत की डिजिटल

व्यक्तिगत डाटा सुरक्षा सुनिश्चित करती है। विनियमन पर बहुत अधिक जोर देने वाले कुछ अंतरराष्ट्रीय प्रारूपों के विपरीत हमारा दृष्टिकोण व्यावहारिक और विकासानुभुती है। यह संतुलन सुनिश्चित करता है कि नागरिकों

पिए गए व्यापक इनपुट जरूर पार्श्वक सर्वोत्तम तौर-तरीकों के अध्ययन का परिणाम है। नागरिकों, व्यवसायों और नागरिक समाज से प्रतिक्रिया और सज्जाव आमंत्रित करते हुए हमने सावेजनिक परामर्श के लिए 45-दिनों की अवधि निर्धारित की है। यह जुड़ाव सामूहिक ज्ञान और भागीदारीपूर्ण नीति निर्माण के महत्व में हमारे विश्वास का प्रमाण है, जबकि यह सुनिश्चित करना

बॉलीवुड / टेली

मसाला

बिंग बॉस से बाहर होकर मायूस दिखीं शिल्पा, जानें किसे विजेता बनते देखना चाहती हैं अभिनेत्री

(आधुनिक समाचार नेटर्वर्क)

नई दिल्ली। बिंग बॉस 18 से

शिल्पा शिरोडकर बाहर हो चुकी थी कि बिंग बॉस में जाना मेरा सपना था जो हैं। घर से निकलने के बाद हाल

से बात करते हुए घर के अनुभव साझा किए। उन्होंने कहा कि बिंग बॉस में जाना मेरा सपना था जो हैं। घर से निकलने के बाद हाल

ये लव स्टोरी वाली फिल्में रही लीक से हटकर, दर्शकों ने भी खूब सराहा

(आधुनिक समाचार नेटर्वर्क)

नई दिल्ली। बॉलीवुड में अधिकतर

फिल्मों में प्रेम कहानियाँ ही होती हैं, जिनकी स्टोरी लाभग्रह एक जैसी नजर आती है। लेकिन समय के

क्या इसके बाद भी इनका प्यार बना रहेगा, यदी फिल्म की कहानी होने वाली है। इस तरह की लीक से हटकर लव स्टोरी पहले भी रहना चाहता है। बनी यानी रणबीर कपूर का किरदार जिंदगी को भरपूर जीना चाहता है। हीरो की यहाँ सोच, उसे उसके प्यार यानी नैना से दूर कर देती है। इस लव स्टोरी फिल्म को भी ऑडियंस ने पसंद किया था क्योंकि कहानी को बड़े ही अलग ढंग से कहा गया। रणबीर कपूर की ही एक फिल्म 'वेक अप सिड' (2009) भी थी, इसमें रणबीर का किरदार एक जिमेदारी ना लेने वाले लड़के का रहा। वहाँ कोकणा सेन शर्मा का किरदार फिल्म में एक महत्वकांकी राइटर का है। वह रणबीर के किरदार को जिंदगी जीना सीखता है, फॉक्स रहने के लिए मोटिवेट करती है। साथ ही इनके बीच एक लव स्टोरी भी चलती है। करीना कपूर और शाहिद कपूर की फिल्म 'जब ती मेट' (2007) भी एक अलग तरह की लव स्टोरी रही। इसमें गीत यानी करीना कपूर का किरदार, शाहिद कपूर के किरदार आदित्य के एक लड़का लड़की के बीच प्यार होता है। लेकिन जब दोनों किसी और रिलेशनशिप में बदलते हैं तो उन्हें अहसास होता है कि वे एक-दूसरे से प्यार करते हैं। फिल्म में इसी कहानी को कभी कमेंटी तो कभी सीरीयस अंदाज में दिखाया। फिल्म में लीड रोल में जेनेविए और इमरान खान नजर आए थे। रणबीर कपूर और दीपिका ने निर्देशित किया था।



साथ बॉलीवुड में ऐसी लव स्टोरी फिल्मों की कहानियाँ भी काफी बढ़ती रही हैं। इसमें लड़कों को यह काफी अलग किस्म हटकर रही है। जल्द ही श्रीदेवी की लव स्टोरी लड़की द्वारा दोस्तों द्वारा होते हैं, वह हमेशा दोस्त रहना चाहते हैं। लेकिन जब दोनों किसी और रिलेशनशिप में बदलते हैं तो उन्हें अहसास होता है कि वे एक-दूसरे से प्यार करते हैं। इसमें जेन जी (उर्हा) जनरेशन की लव स्टोरी के बीच प्यार होता है लेकिन शादी से पहले लड़की के पापा शर्त रखते हैं कि दोनों अपना फोन अदल-बदल लें।

पादकोण स्टारर फिल्म 'ये जावनी

नई दिल्ली' (2013) में भी हीरो

अपनी शर्तों पर जिंदगी जीना

चाहता है, वह कर्हीं बंधकर नहीं

रहना चाहता है। बनी यानी

रणबीर कपूर का किरदार जिंदगी

को भरपूर जीना चाहता है। हीरो

की यहाँ सोच, उसे उसके प्यार

यानी नैना से दूर कर देती है।

इस लव स्टोरी फिल्म को भी

ऑडियंस ने पसंद किया था क्योंकि

कहानी को बड़े ही अलग ढंग से

कहा गया। रणबीर कपूर की ही

एक फिल्म 'वेक अप सिड' (2009)

भी थी, इसमें रणबीर का किरदार

एक जिमेदारी ना लेने वाले लड़के

का रहा। वहाँ कोकणा सेन शर्मा

का किरदार फिल्म में एक

महत्वकांकी राइटर का है। वह

रणबीर के किरदार को जिंदगी

जीना सीखता है, फॉक्स रहने

के लिए मोटिवेट करती है। साथ

ही इनके बीच एक लव स्टोरी भी

चलती है। करीना कपूर और

शाहिद कपूर की फिल्म 'जब ती

मेट' (2007) भी एक अलग तरह

की लव स्टोरी रही। इसमें गीत

यानी करीना कपूर का किरदार,

शाहिद कपूर के किरदार आदित्य

को जिंदगी से फिल्म से प्यार करना

एवं जिमेदारी ना लेने वाले लड़के

का रहा। वहाँ कोकणा सेन शर्मा

का किरदार फिल्म में एक

महत्वकांकी राइटर का है। वह

रणबीर के किरदार को जिंदगी

जीना सीखता है, फॉक्स रहने

के लिए मोटिवेट करती है। अब

तक इनके बीच एक लव स्टोरी

चलती है। करीना कपूर पर बुधवार को

जिंदगी की लव स्टोरी होती है।

जिंदगी की लव स्टोरी होती है।